(b) if so, what steps have been taken by Government to test the efficacy thereof and with what results; and

(c) what steps are being taken to undertake production and marketing thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को एक अत्याधुनिक एकक बनाए जाने के लिए सहायता

*80. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री राम नरेश यादव:

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा, दिल्ली में बिजली सप्लाई की वितरण व अनुरक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए संस्थान को अत्याधुनिक बनाए जाने की अपनी योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने के लिए हाल ही में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ बातचीत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में वित्तीय प्रशासन में कुप्रबंध के कारण विश्व बैंक के अधिकारियों ने फिलहाल वित्तीय सहायता देने में अपनी असहमति व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा संस्थान में व्याप्त कुप्रबंध को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली के चारों ओर 400 के० वी० पारेषण रिंग स्थापना से संबंधित योजना के क्रियान्वयन का वित्तपोषण करने के लिए डेसू द्वारा वर्ष 1987 में विश्व बैंक के साथ 60 मिलियन डालर के मूल्य के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। यह समझौता इस शर्त पर है कि डेसू कुछ निश्चित प्रसंविदाएं पूरा करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसके द्वारा 31 दिसम्बर, 1988 तक एक वसूली योजना बनाया जाना एवं उसका कार्यान्वयन किया जाना शामिल है। डेसू की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अब एक कार्रवाई योजना तैयार की गई है। बैंक द्वारा ऋण का संवितरण अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया गया है।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Discontentment among the Employees of Public Sector

482. SHRI MOHAMMED AMIN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the serious discontentment among the public sector employees in the country;

(b) if so, what are there grievances at present;

(c) what steps Government have taken or propose to take to redress their grievances;

(d) whether Government will take immediate steps so that a confrontation is avoided in the immediate future; and

(e) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) to (e) The main reason for the discontentment among the public sector employees is the delay in finalisation of long-term wage settlements. Government have already laid down a wage policy and the Managements of public sector enterprises and the workers have to finalise wage settlements within the parameters of the wage policy bilaterally. However Govt, have also emphasised the need for the PSUs to finalise the wages settlements quickly.

Surplus production of Cement

483. SHRI BAIKUNTHA NATH SAHU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the projection of production, supply and demand of cement during the years 1988-89 and 1989-90;

(b) whether there will be surplus production of cement in the country by the end of the Seventh Five Year Plan;

(c) if so. what steps are proposed to be taken to utilise the surplus cement; and

(d) whether Government will export cement if production increased further?